राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 897/2010/जयपुर.

मैसर्स डी.सी.एम. श्रीराम कंसोलिडेटेड लिमिटेड,
एम. आई. रोड़, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत राज. जयपुर.
2. उपायुक्त (अपील्स)–IV, वाणिज्यिक कर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12/08/2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 228/अपील्स–II/07–08/जयपुर–बी में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 10.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (जिसे आगे **'प्रोत्साहन योजना'** कहा जायेगा) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा हकदारी प्रमाण–पत्र पुस्तक संख्या 2 क्रमांक 26 दिनांक 05.12.2005 जारी किया गया है, जिसके तहत व्यवहारी को विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिये फर्टीलाईजर प्लांट के अतिरिक्त 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिनांक 07.02.2005 से 7 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया। आयुक्त, उद्योग विभाग के संशोधन आदेश दिनांक 23.06.2006 से ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत को संशोधित कर 75 प्रतिशत किया गया। उक्त प्रमाण–पत्र व संशोधन के प्रभाव से अपीलार्थी इकाई को पूर्ववर्ती 3 वर्षों में जिस वर्ष में अधिकतम कर देय अथवा भुगतान किया गया है, में से जो राशि अधिक है, चालू वर्ष में उस राशि पर आधिक्य के रूप में देय या भुगतान किये गये ब्याज में 5 प्रतिशत तक की राशि तक ही सीमित है। अपीलार्थी द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में से वर्ष 2003–04 में देय एवं भुगतान की गयी कर राशि रूपये 6,03,24,992/– सर्वाधिक है, अतः इसे आधार वर्ष की देय कर

लगातार................2

राशि स्वीकृत कर आगामी वर्षों के लिये उक्त राशि से अधिक भुगतान राशि के सम्बन्ध में ब्याज अनुदान अनुज्ञेय माना गया। अपीलार्थी इकाई को वर्ष 2006—07 की प्रथम, द्वितीय व तृतीय तिमाही के लिये कुल ब्याज अनुदान रूपये 5,63,97,084/— पूर्व में ही स्वीकृत किया जा चुका था। अपीलार्थी इकाई द्वारा चतुर्थ तिमाही के लिये दावा रूपये 2,22,30,104/— का पेश किया गया। सम्पूर्ण वर्ष की वार्षिक ब्याज अनुदान की गणना करने पर पाया कि आलौच्य अवधि में इस नीति के अन्तर्गत पात्र इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों पर देय कर दर अनुसार वर्ष भर का कुल कर रूपये 16,58,29,303/— बनता है। इस राशि में आई.टी.सी., रिवर्स टैक्स एवं अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के अनुसार अनुज्ञेय आंशिक कर मुक्ति राशि आदि राशियों को समायोजन करने के पश्चात देय कर रूपये 15,22,44,881/— बनता है। इस राशि में से आधार वर्ष की देय कर राशि रूपये 6,03,24,992/— को कम किये जाने पर आधार वर्ष की तुलना में आधिक्य कर भुगतान रूपये 9,19,19,889/— आता है। इस राशि पर नीति में जारी पात्रता प्रमाण—पत्र दिनांक 5.12.2005 एवं संशोधन आदेश दिनांक 23.06.2006 के अनुसार 75 प्रतिशत से ब्याज अनुदान रूपये 6,89,39,917/— अनुज्ञेय है, जिसमें से आदेश क्रमांक 835 दिनांक 10.10.2006 एवं आदेश क्रमांक 134 दिनांक 02.03.2007 से रूपये 1,97,66,857/— कुल रूपये 5,63,97,084/— का अनुदान पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। अतः चतुर्थ तिमाही में इस आदेशानुसार आलौच्य अवधि के लिये शेष अनुदान राशि रूपये 1,25,42,833/— (6,89,93,917 — 5,63,97,084) का ही ब्याज अनुदान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य माना गया। अतः अपीलार्थी द्वारा रूपये 93,15,342/— के ब्याज अनुदान को विवादित करते हुए अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05.03.2010 से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा अपीलार्थी इकाई को प्रोत्साहन योजना के तहत पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत ब्याज अनुदान पूंजी विनिवेश को प्रोत्साहित करने के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रोत्साहन योजना के क्लॉज 7(बी) के अनुसार अपीलार्थी ब्याज अनुदान प्राप्त करने का हकदार है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज अनुदान राशि में से आई.टी.सी. को समायोजित करते हुए तदनुसार ब्याज अनुदान स्वीकृत किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। वेट अधिनियम की धारा 18 के तहत आई.टी.सी. अनुज्ञेय है, जो कि अपीलार्थी द्वारा अपने विक्रेता व्यवहारी से माल क्रय किये जाने पर

चुकाये गये वैट से सम्बन्धित है। ब्याज अनुदान राशि में से आई.टी.सी. को समायोजित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अग्रिम कथन किया कि प्रोत्साहन योजना, वेट अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व प्रभावी होने से वेट अधिनियम के प्रावधान इस पर लागू किया जाना प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के प्रथम तीन तिमाही में नियमानुसार ब्याज अनुदान स्वीकृत किया गया है, जबकि चतुर्थ तिमाही में ब्याज अनुदान में कटौती किये जाने का कोई आधार नहीं होते हुए भी ब्याज अनुदान में कमी किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का समुचित विश्लेषण किये बिना कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **32 टैक्स अपडेट 164 मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य** को उद्धरित करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि प्रोत्साहन योजना के अधीन अनुदान राशि की गणना करने हेतु 'Tax payable' राशि की गणना का आधार क्या होगा या 'Tax payable' राशि क्या होगी ? इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन योजना के क्लॉज 7 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

7. SUBSIDIES:

(i) (a) In case of new investments made, the sum total of interest subsidy and wage/employment subsidy would be subject to a maximum limit of fifty percent of the tax payable and deposited under the Rajasthan Sales Tax Act, 1994, the Central Sales Tax Act, 1956 and Value Added Tax Act as and when introduced in the State.

(b) In case of investment made in Modernization / Expansion /Diversification, the amount of subsidy shall be subject to a maximum of fifty percent of the additional amount of Rajasthan Sales Tax and the Central Sales Tax or VAT payable or deposited by the unit over and above the highest tax payable or deposited whichever is higher, in any of the three immediately preceding years.

लगातार.....4

provided that the maximum limit of fifty percent prescribed under clause 7(i)(a) and clause 7(i)(b) may be raised by the BIDI (Board of Infrastructure Development & Investment Promotion, Government of Rajasthan) to sixty percent in such cases where the investments exceed Rs. 100 crores but are less than or equal to Rs. 200 crores; and this maximum limit may be raised further to seventy five percent in cases where the investments exceed Rs. 200 crores.

and provided further that the maximum limit of 50% prescribed under clause 7 (i) a and clause 7 (i) b shall be raised up to 75% for the Biotechnology Unit established in terms of the Biotechnology Policy, 2004.

[provided also that for the new investment in **textile sector,** the maximum limit of 50% prescribed under clause 7(i)(b) shall stand raised to, sixty percent in such cases where such investment exceeds Rs. 50 crores but is less than or equal to Rs. 100 crores and to seventy five percent in cases where such investment exceeds Rs. 100 crores.]

(ii) Subject to clause (i), interest subsidy shall be 5% (percentage points). An additional interest subsidy of one percent shall be available to Schedule Caste/Schedule Tribe entrepreneurs. In case the documented rate of interest is less than 5% or less than 6% in case of SC/ST entrepreneurs, the entitlement of the interest subsidy will be limited to the documented rate of interest and the amount actually paid as interest but shall not include penal interest.

(iii) The Subsidy shall be available to the investors for seven years from the date of first repayment of interest in case of Interest Subsidy, and first payment of wages/employment in case of wage employment subsidy. In case of Expansion / Modernization / Diversification, the unit shall be eligible for subsidy under the scheme from the date of payment of sales tax over and above the highest sales tax paid in the immediately preceding three years before such Expansion / Modernization / Diversification,

(iv) Where a unit has claimed and/or is availing benefit of the Interest Subsidy, the Wage/Employment Subsidy shall be available to the extent of twenty five percent of wages/salary paid by the investors to workers for whom the employee and employers are both contributing in the approved provident funds. However, in case of the unit is not claiming or availing Interest Subsidy, the amount of wage/employment subsidy shall be thirty percent of the wages/salary paid to the workers for whom the employee and employer are contributing for the approved provident funds,

provided however that notwithstanding anything contained in this clause, wage/employment subsidy in the case of diversification/expansion or modernisation shall be available only with respect to additional numbers of such workers engaged for whom the employee and the employer are both contributing in the approved provident funds,

and provided further that such additional number of workers in the case of diversification, modernisation or expansion is at least twenty five percent of the existing direct employment subje ct to a minimum of ten additional persons as already provided under Clause 5(a)(iii)(b) of this Scheme.

(v) For Interest Subsidy the interest actually being paid on the additional capital borrowed shall be the only basis for the computation of subsidy. In case of Wage/Employment Subsidy the wages/salary paid for the additional employment generated shall be the basis for the computation of Wage/Employment Subsidy.

[(vi) Notwithstanding anything contained in sub clauses (i) to (v) above, in case of new cement unit having investment exceeding Rs. 400 crores and with a minimum regular employment of 200 persons, the amount of subsidy shall be subject to a maximum limit of 75% of the tax payable or deposited under Rajasthan Sales Tax, 1994 or Value Added Tax Act (as and when introduced in the State) and Central Sales Tax Act, 1956 for a period of 7 years from the date of the commencement of production, subject to the following conditions, namely –

1. The investor shall submit an option to the Member Secretary, SLSC to avail benefit under this scheme within 180 days of this amendment;
2. The unit shall start commercial production within 5 years of filing of application for option; and
3. The sum total of 75% subsidy shall be calculated in the following manner: -
   (a) Subsidy of 45% of the Rajasthan Sales Tax or Value Added Tax and Central Sales Tax shall be allowed upfront on the basis of actual tax liability; and \
   (b) The remaining subsidy to the extent of 30% of Rajasthan Sales Tax or Value Added Tax and Central Sales Tax liability shall be allowed in form of interest subsidy, wage/employment subsidy out of which interest subsidy shall be limited to 5% of the documented rate of interest and the amount actually paid as interest shall not include penal interest, and wage/employment subsidy. A unit not claiming any interest subsidy can claim wage/employment subsidy to the extent of 30% subject to other conditions under this amendment.

-393

लगातार.....6

4. The claim of subsidy shall be as per the provisions of this Scheme.

"(vii) Notwithstanding anything contained in sub clauses (i) to (v) above, in case of investments for expansion of existing cement unit having investment exceeding Rs. 200 crores and with a minimum regular employment of 100 persons, the amount of subsidy shall be subject to a maximum limit of 75% of the additional tax (calculated by taking the average of last 3 years) payable or deposited under Rajasthan Sales Tax Act, 1994 or Value Added Tax Act (as and when introduced in the State) and Central Sales Tax Act, 1956 for a period of 7 years from the date of commencement of production, subject to the following conditions, namely–

1. The investor shall submit an option to the Member Secretary, SLSC to avail benefit under this scheme within 180 days of this amendment;
2. The unit shall start commercial production within 5 years of filing of application for option; and
3. The sum total of 75% subsidy shall be calculated in the following manner: -
   (a) Subsidy of 45% of the Rajasthan Sales Tax or Value Added Tax and Central Sales Tax shall be allowed upfront on the basis of actual tax liability; and
   (b) The remaining subsidy to the extent of 30% of Rajasthan Sales Tax or Value Added Tax and Central Sales Tax liability shall be allowed in form of interest subsidy, wage/employment subsidy out of which interest subsidy shall be limited to 5% of the documented rate of interest and the amount actually paid as interest shall not include penal interest, and wage/employment subsidy. A unit not claiming any interest subsidy can claim wage/employment subsidy to the extent of 30% subject to other conditions under this amendment.
4. The claim of subsidy shall be as per the provisions of this Scheme.]

7. अपीलार्थी ने वर्ष 2006–07 के चतुर्थ त्रैमास के लिये ब्याज अनुदान का दावा रूपये 2,22,30,104/– का प्रस्तुत किया, जिसमें 'input tax credit' की राशि घटाई हुई नहीं थी। कर निर्धारण अधिकारी ने tax payable की राशि आंकलित करने के लिये input tax credit की राशि घटाते हुए tax payable राशि की गणना की। Tax payable की गणना करने के लिये रूपये 93,15,342/– की input tax credit को output tax/tax leviable में से घटाया गया।

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 32 टैक्स अपडेट 164 मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य के पैरा संख्या 2, 6 व 7 में निम्न व्यवस्था दी गयी है :–

लगातार.....7

2. Clause 7 of the Rajasthan Investment Promotion Policy, 2003 (RIPS 2003, for short) provides that in case of new investment made, the sum total of interest subsidy and wage/employment subsidy would be subject to a maximum limit of fifty percent of the **tax payable and deposited** under the Rajasthan Sales Tax Act, 1994, the Central Sales Tax Act, 1956 and Value Added Tax Act as and when introduced in the State. The Rajasthan VAT Act, 2003 was enforced w.e.f. 1.4.2006 during the operative period of RIPS, 2003, which was extended upto 31.3.2011. Clause 7(i)(a) of the Scheme reads as under:

"**7. SUBSIDIES**

(i)(a) the sum total of interest subsidy and wage/employment subsidy would be subject to a maximum limit of **fifty percent of the tax payable and deposited** under the Rajasthan Sales Tax Act, 1994, the Central Sales Tax Act, 1956 and Value Added Tax Act as and when introduced in the State."

2. The impugned clarification issued by the Tax Division of the Finance Department of Government of Rajasthan on 10.10.2008 is also reproduced hereunder in extenso for ready reference:

"GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE DEPARTMENT

(TAX DIVISION)

No.F.4(18)FD/Tax.Div./2001 Jaipur dated 10.10.2008

The Government launched the Rajasthan Investment Promotion Scheme, 2003 vide this Department's order No. F.4(18) FD/Tax-Div./2001 dated 28.7.2003 (amended from time to time) hereinafter referred to as 'the Scheme'. It has been brought to the notice of the Government by Commercial Tax Department that there are some issues which need interpretation of certain clauses of the Scheme. After examination of the issues, to bring in more clarity the issues are clarified under clause 11 of the Scheme, as under:-

CLARIFICATIONS

1. Regarding periodicity for computation of subsidy under the Scheme, it is clarified that **computation** of subsidy under the Scheme shall be made **on quarterly basis** after submission of return for the quarter along with proof of deposit of tax. It is further clarified that subsidy under clause 7 is allowable **after deposit of the tax**.

2. The term 'year', occurring in the scheme, mean financial year.

3. The term '**tax payable**' under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, is the amount of **tax leviable** under the Act **less** the amount of **input tax credit**, if any, for the purpose of the Scheme.

-3693

लगातार.....8

4. Under Incentive Schemes of 1987, 1989, and 1998 the goods manufactured by such units are not exempted but the units are exempted from payment of tax under the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 and the Rajasthan Sales Tax Act, 1994. As such 'Tax payable' by such units is the amount of tax leviable on the taxable turnover.

5. In case of the unit availing benefit of deferment of tax, part of tax payable is deposited by the unit and part of it is deferred for stipulated period which is paid later on in installments. In such cases it is clarified that the amount of subsidy shall be divided in proportion to the tax payable under sub-section (1) of section 20 of RVAT Act, 2003 and the amount of tax deferred under subsection (3) of section 20 of RVAT Act, 2003. **The proportionate amount of subsidy shall be allowed against the tax** payable under sub-section (1) of section 20 of RVAT Act, 2003 on the basis of quarterly returns. The proportionate amount of subsidy shall be allowed at the time of deposit amount of deferred tax subsection (3) of section 20 of RVAT Act, 2003.

6. Where the unit is engaged in trading of goods, other than the goods manufactured by it, subsidy is allowable **only on the amount of tax payable on the sale of goods manufactured by such unit.**

By order
Sd/-
(Aditya Pareek)
Deputy Secretary to Government"

6. The learned counsel for the petitioner submitted that the terms 'output tax', input tax', 'reverse tax' and 'tax period' have been defined in Rajasthan VAT Act, 2003 in section 2(17), 2(24), 2(33) and 2(39) of the Act and the terms ' tax payable' as such has not been defined under the Act. He, therefore, submitted that higher interest subsidy would be payable to the assessee and the under the garb of clarification dtd.10.10.2008, such limit of 50% could not be referred to the 'net tax payable' as has been done under Clause 2 of the impugned clarification dtd.10.10.2008.

7. On the other hand, Mr.V.K. Mathur, learned counsel for the Revenue submitted that the tax payable by a dealer under the Rajasthan VAT Act, 2003 has been defined in Section 17 of the VAT Act, 2003 which stipulates that 'tax payable' under the said Act is 'net tax payable' by a registered dealer for a tax period computed by formula; T =(O+R+P) - I where T is net tax payable; O is amount of output tax, R is amount of reverse tax and P is the amount of tax payable under sub-section (2) of section 4; and I is the amount of input tax. He also submitted that power to issue such clarification by the Finance Department and Tax Division is clearly there in clause 11 of the RIPS, 2003 and power to review, appeal and revision by the State Government are contained in clauses 11, 12, 13 and 14 of the RIPS, 2003 respectively. Said clauses are reproduced herebelow for ready reference :

-3692

लगातार.....9

"11. AUTHORITY FOR IMPLEMENTATION/ INTERPRETATION:

All the related departments shall implement the scheme. The **Industries Department shall act as the nodal coordinating, monitoring and implementing department.** Any matter pertaining to **interpretation of any Clause of the Scheme shall be referred to the Government of Rajasthan in the Finance Department whose decision shall be final** in such a matter.

12. REVIEWS AND APPEAL:

The State Level Screening Committee and District Level Screening Committee, described under clause 6 of this Scheme, shall also be empowered to review their decision. The State Level Screening Committee shall hear and decide appeals against the orders of District Level Screening Committee. Provided that the aggrieved party has filed review application or the appeal within the period of 60 days from the date of communication of the decision of the committee.

13. REVISION BY THE STATE GOVERNMENT:

(a) The State Government in Finance Department may suo motu or otherwise revise an order passed by any Screening Committee wherever it is found to be erroneous and prejudicial to the interest of the State revenue, after affording an opportunity of being heard to the beneficiary industrial unit.

(b) No order under the sub-clause (a) shall be passed by the State Government after the expiry of a period five years after the date by which the benefits under this scheme are fully availed of.

14. REVIEW OR MODIFICATION OF SCHEME:

The State Government in the Finance Department reserves the right to review or modify the Scheme as and when needed in public interest."

9. माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार प्रोत्साहन योजना में वित्त विभाग (कर अनुभाग) राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2008 को दिया गया स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 सपठित प्रोत्साहन योजना के क्लॉज 7 के पूर्ण सामंजस्य/अनुरूपता में है।

10. इस स्पष्टीकरण का निर्वचन न तो अशुद्ध है, ना ही त्रुटिपूर्ण है। इस स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार tax payable वह राशि है जो tax leviable में से input tax credit की राशि घटाने के बाद आता है। अनुदान एक रियायत है तथा अनुदान अपीलार्थी का कोई निहित अधिकार नहीं है।

— 363

लगातार.............10

11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में दी गई व्यवस्था के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि प्रोत्साहन योजना में अनुदान राशि की गणना के लिये tax payable राशि की गणना के लिये tax leviable में से input tax credit की राशि घटाने के पश्चात आई राशि ही अनुदान गणना का आधार होगी।

12. इसी निर्णय को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अनुदान राशि की गणना की है। अतः कर निर्धारण आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है, इसी प्रकार अपीलीय आदेश में भी कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

13. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 05.03.2010 की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 12.08.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(बी. के. मीणा)
अध्यक्ष